

## MSP को वैधानिक बनाने की किसानों की मांग

### प्रलिस के लिये:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [न्यूनतम समर्थन मूल्य](#), [आर्थिक उदारीकरण](#), [वशिव व्यापार संगठन](#), [खाद्य मुद्रासफीति](#), [प्रधानमंत्री अननदाता आय संरक्षण अभियान](#), [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना](#)

### मेन्स के लिये:

भारत में कृषि नीतियाँ, कृषि से संबंधित आर्थिक चुनौतियाँ, किसानों का वरिध, कृषिविधिीकरण एवं स्थरिता

[स्रोत: लाइवमटि](#)

### चर्चा में क्यों?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा हाल ही में प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत न करने एवं उनकी शिकायतों का समाधान न करने के लिये केंद्र सरकार की आलोचना की गई।

- न्यायालय ने केंद्र से [न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\)](#) के लिये वधिक गारंटी की मांग वाली नई याचिका पर जवाब देते हुए किसानों की मांगों पर वधिार करने का आग्रह किया।
- यह घटनाक्रम पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसान समूहों द्वारा लंबे समय से चल रहे वरिध प्रदर्शन से संबंधित है।

### MSP गारंटी से संबंधित याचिका क्या है?

- याचिका: इसमें [कृषिकानूनों](#) को नरिसत करने के बाद [वर्ष 2021 के किसान वरिध प्रदर्शन](#) के दौरान किए गए वादों के आधार पर फसलों पर MSP हेतु वधिक गारंटी की मांग की गई।
  - इस याचिका में मांग की गई है कि कृषि उत्पादकों के लिये [स्थरि आय सुनश्चिति करने के क्रम में MSP](#) को वधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रत्यक्ष आदेश जारी न करते हुए, इस मुद्दे को सुलझाने के लिये उच्चाधिकार प्राप्त समति का उपयोग करने का सुझाव दिया तथा इस संदर्भ में केंद्र से तुरंत जवाब देने को कहा।
  - इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी से चल रहे वरिध प्रदर्शनों को वधिक बल मलिन के साथ अधिक व्यवस्थित तथा वधिक समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

### भारत में किसानों के वरिध प्रदर्शन का क्या कारण है?

- [किसानों के वरिध प्रदर्शन का कारण](#): यह वरिध प्रदर्शन [भारत के वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण](#) से संबंधित लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से प्रेरित है, जिसमें कृषि की तुलना में औद्योगीकरण को प्राथमकता दी गई थी।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ किसान कम फसल लाभ एवं बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं) में संकट बढ़ रहा है।
  - यद्यपि सरकार कई फसलों के लिये MSP नरिधारित करती है लेकिन इसका क्रयान्वयन सीमति है तथा इसके तहत खरीद ज्यादातर चावल एवं गेहूँ की ही होती है।
    - किसान (वशिषकर गैर-प्रमुख फसल क्षेत्रों के संदर्भ में) अक्सर उत्पादन लागत से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं।
  - [वशिव व्यापार संगठन \(WTO\)](#) के समझौते (जनिहें प्रायः [मुक्त व्यापार को बढ़ावा](#) देने वाले समझौतों के रूप में देखा जाता है), [व्यापार प्रतबंध लगाने या किसानों को सब्सिडी प्रदान करने की भारत की क्षमता](#) को सीमति करते हैं।
    - प्रदर्शनकारियों के अनुसार, इससे किसानों के लिये खरीद नीतियाँ एवं सब्सिडी को नरियंत्रित करने की भारत की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।

- **किसानों की प्रमुख मांगें:** प्राथमिक मांग एक ऐसे कानून की है जो सभी फसलों के लिये MSP की गारंटी देता है।
  - यह **स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट** पर आधारित है, जिसमें 'C2+50%' फार्मूले का उपयोग करते हुए उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जिन की सफाई की गई है।
    - **व्यापक लागत (C2)** में सभी भुगतान किये गए व्यय, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, करिया, तथा स्वामित्व वाली भूमि और स्थायी पूंजी पर छोड़ा गया ब्याज शामिल है।
    - जबकि **MSP वर्तमान में A2+FL से 50% अधिक निर्धारित है**, जिसमें भुगतान किये गए व्यय और अवैतनिक पारिवारिक श्रम शामिल हैं।
  - **अन्य प्रमुख मांगें: किसानों और मजदूरों के लिये पूर्ण ऋण माफी।** किसानों के लिये मुआवज़ा और पेंशन, विशेष रूप से वरिष्ठ प्रदर्शन या कृषि संकट से प्रभावित किसानों के लिये।
    - कृषि श्रमिकों के लिये बेहतर कार्य स्थितियाँ और मजदूरी।
    - भूमि और जल पर **स्वदेशी लोगों के अधिकारों** का संरक्षण।
- **सरकार का दृष्टिकोण:** केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि **MSP के लिये कानूनी गारंटी देना अव्यवहारिक होगा**, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और खरीद की उच्च लागत शामिल है।
  - सरकार ऐसी नीतिके आर्थिक प्रभावों को लेकर भी चिंतित है, जिसमें **खाद्य मुद्रासफीति** और **बजटीय बाधाएँ** शामिल हैं।

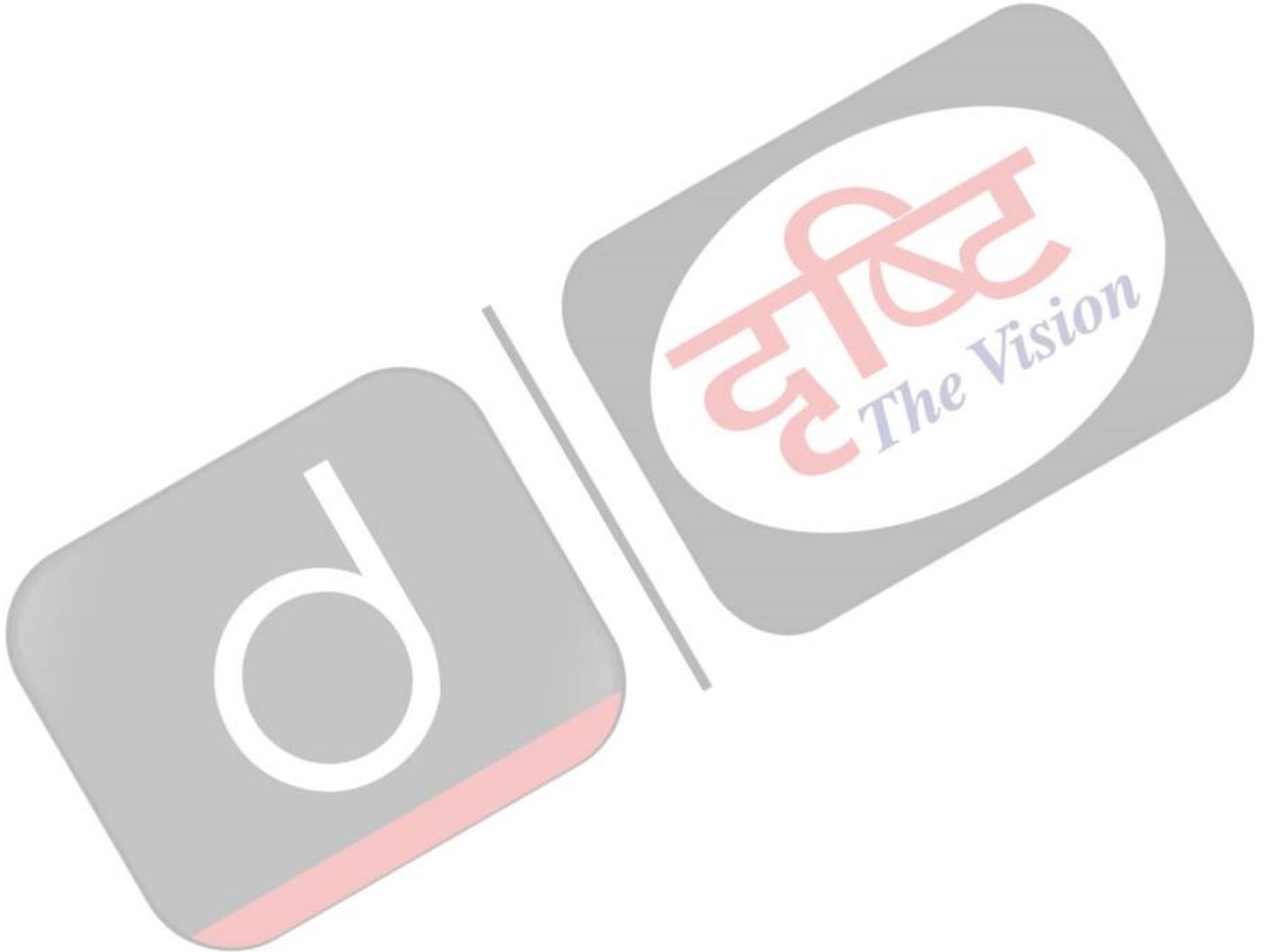
## MSP के वैधता के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

- **MSP के वैधता के पक्ष में तर्क:**
  - **किसानों की परेशानी का समाधान:** MSP को वैध बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी फसलों के लिये उचित मूल्य मिले, बाज़ार में उतार-चढ़ाव से होने वाले कम लाभ की समस्या दूर होगी तथा उत्पादन लागत को कवर करके और किसानों के लिये उचित लाभ की गारंटी देकर **वित्तीय सुरक्षा** प्रदान की जाएगी।
    - **भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 15% से नीचे गिर गया है**, तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद **किसानों की आय में न्यूनतम वृद्धि हुई है**।
      - MSP को वैधानिक बनाने से उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि विकास को समर्थन देकर इस अंतर को कम किया जा सकता है।
  - **औपचारिक बाज़ारों को बढ़ावा देना:** MSP को वैध बनाने से औपचारिक बाज़ार लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, अनौपचारिक बाज़ारों पर निर्भरता कम होगी, तथा **डिजिटल कृषि के माध्यम से पारदर्शिता** बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य के साथ तालमेल हो सकेगा।
  - **स्थिर बाज़ार मूल्य:** MSP को वैध बनाने से कृषि बाज़ार में **मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है**, जिससे कृषि आय और उपभोक्ता मूल्य दोनों स्थिर हो सकते हैं।
  - **लागत गणना विधियाँ:** लागत गणना की वर्तमान विधियाँ प्रायः **कृषि की वास्तविक लागत को दर्शाने में विफल रहती हैं**, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें किसानों के व्यय से भी कम हो जाती हैं।
    - अधिक सटीक मूल्य निर्धारण मॉडल, जैसे कि C2+50% पद्धति, कृषि मूल्यों को अन्य क्षेत्रों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित कर सकती है।
  - **कृषि निवेश:** MSP को वैध बनाने से **किसानों को पूरवानुमानित आय प्राप्त होगी**, कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा **सतत पद्धतियों और हरित प्रौद्योगिकियों** के माध्यम से उत्पादकता में सुधार होगा।
- **MSP के वैधता के विपक्ष तर्क:**
  - **तार्किक चुनौतियाँ:** देश भर में सभी फसलों पर MSP लागू करना **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण कठिन है**, जैसे कि मंडी प्रणाली, जो कई राज्यों में क्रियाशील नहीं है।
  - **सरकार के लिये उच्च लागत:** सभी फसलों को **MSP पर खरीदने के लिये अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी**, जिससे बजटीय बाधाएँ और संभावित आर्थिक तनाव बढ़ेंगे।
  - **खाद्य मुद्रासफीति:** **MSP के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं**, जिससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे, विशेषकर यदि सरकार को सभी फसलों को MSP पर खरीदने के लिये बाध्य किया जाए।
  - **बाज़ार में बाधाएँ:** MSP का सांविधिकरण कृषि बाज़ारों में **आपूर्ति और मांग की वर्तमान गतिशीलता को बाधित** कर सकता है, जिससे अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - **वैश्व व्यापार संगठन की बाधाएँ:** वैश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते सरकार की **सब्सिडी प्रदान करने या कृषि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने** की क्षमता को सीमित करते हैं, जिससे MSP के सांविधिकरण की प्रभावशीलता कमज़ोर हो सकती है।

## देश भर में MSP को वैध बनाने के विकल्प क्या हो सकते हैं?

- **लक्षित दृष्टिकोण:** फसलों के एक छोटे प्रतिशत के लिये MSP के सांविधिकरण से खरीद प्रणाली को प्रभावित किये बनी कीमतों को स्थिर किया जा सकता है।
  - **इसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)** द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जो MSP और मूल्य न्यूनता भुगतान के माध्यम से किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।
  - **मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा** जैसे कुछ राज्यों ने खरीद प्रणालियों का सफलतापूर्वक विस्तार किया है।
    - क्षेत्रीय कृषि चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये, राष्ट्रव्यापी स्तर पर MSP को वैध बनाने के बजाय **स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट कानून** बनाने पर विचार किया जा सकता है।
- **सहकारिता की भूमिका:** एक विकल्प के रूप में **सहकारी समितियों और FPO को बढ़ावा देना**, जो **दूध उत्पादन** जैसे कुछ क्षेत्रों में सफल रहे हैं।

- **सहायक बुनयादी ढाँचा:** सहकारी समितियों और FPO के लिये एक मज़बूत कानूनी ढाँचा, आधुनिक भंडारण सुविधाएँ एवं बेहतर बुनयादी ढाँचा आवश्यक है।
  - प्रधानमंत्री **किसान सम्पदा योजना (PMKSY)** बुनयादी ढाँचे को बढ़ाकर तथा **फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान को कम करके** इसकी पूर्ति कर सकती है।
- **अनुबंध खेती: किसानों और नगिमों** या सहकारी समितियों के बीच अनुबंधों को प्रोत्साहित करना, जहाँ किसान अपनी उपज के लिये गारंटीकृत मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
- **फसल बीमा योजनाएँ: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** जैसी पहलों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं या बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिये फसल बीमा का वस्तु और सुधार करना।
- **विविधीकरण:** किसानों को अपनी फसलों और आय स्रोतों में विविधता लाने के लिये प्रोत्साहित करना, जिससे कुछ फसलों पर उनकी निर्भरता कम हो सके, जिससे बाज़ार में अस्थिरता आती हो।



# MINIMUM SUPPORT PRICE (MSP)

The rate at which the govt. purchases crops from farmers; based on a calculation of at least 1.5x the cost of production incurred by the farmers

## RECOMMENDED BY

Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) (recommends MSPs for 22 mandated crops and Fair and Remunerative Price for Sugarcane)

## 22 MANDATED CROPS

(14 Kharif, 6 Rabi and 2 Other Commercial crops)

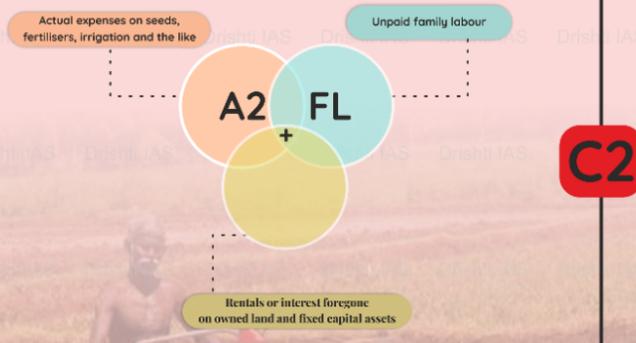
7	<b>CEREALS</b>	Paddy, Wheat, Barley, Jowar, Bajra, Maize And Ragi
5	<b>PULSES</b>	Gram, Arhar/tur, Moong, Urad And Lentil
7	<b>OILSEEDS</b>	Groundnut, Rapeseed/mustard, Soyabean, Sunflower, Sesamum, Safflower And Niger Seed
	<b>RAW COTTON</b>	
	<b>RAW JUTE</b>	
	<b>COPRA</b>	

MSP is the price at which the govt. is supposed to procure the mandated crops from farmers if the market price falls below it

## FACTORS FOR RECOMMENDING MSP

- ▶ Cost of cultivation
- ▶ Demand-Supply situation for the crop
- ▶ Market price trends
- ▶ Inter-crop price parity
- ▶ Implications for consumers (inflation)
- ▶ Environment (soil and water use)
- ▶ Terms of trade b/w agri and non-agri sectors (ratio of farm inputs and outputs)

Considers both A2+FL and C2 costs



MSP has no statutory backing — a farmer cannot demand MSP as a matter of right



Drishti IAS

